



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23—जनवरी 29, 2016 (माघ 3, 1937)

No. 4]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23—JANUARY 29, 2016 (MAGHA 3, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	135
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	55
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	165
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	*

\*अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	पृष्ठ सं.
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	125
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	17
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	45
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के अंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

## CONTENTS

Page No.		Page No.	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	135	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	55	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	165	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	125
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	17
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	45
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

### [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की  
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and  
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2016

संकल्प

सं. 6/5/2015—टीयूएफएस—देश में व्यवसाय करने को आसान बनाने और रोजगार सृजन के लिए सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने तथा 'मेक इन इंडिया' और विनिर्माण में जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभों और इसके अंतर्गत लाभों का दावा करने की क्रियाविधि के संबंध में मौजूदा संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिक उन्नयन योजना (आरआरटप्स) में संशोधन किया जाना चाहिए। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटप्स) नामक नई योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जो निर्यात और आयात संस्थाओं के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए रोजगार और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्र के वस्त्र मूल्य श्रृंखला में निवेश करने के लिए एक मुश्त पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। यह योजना क्रेडिट लिंक्ड होगी और ऋणदाता एजेंसियों द्वारा स्वीकृत आवधिक ऋणों की निर्धारित सीमा में शामिल प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाएं ही इसके अंतर्गत लाभ प्रदान करने की पात्र होंगी।

2. यह योजना इस संकल्प के जारी होने की तारीख से 7 वर्षों के लिए 31.03.2022 तक प्रभावी होगी। तथापि वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करने के लिए सितम्बर, 2014 से लंबित मामले मौजूदा आरआरटप्स के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।

3. कंपनियों के पंजीयक के पास कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एकल कंपनियों/इकाइयों, उन एमएसएमई इकाइयों को छोड़कर जिन्हें एमएसएमई मंत्रालय अथवा संबंधित उद्योग निदेशालय अथवा उपयुक्त केंद्रीय/राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाएगा, ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

4. प्रत्येक एकल कंपनी नीचे दर्शाई गई दरों तथा अधिकतम सब्सिडी सीमा के अनुसार पात्र निवेश पर केवल एक बार पूंजीगत सब्सिडी हेतु पात्र होंगे :

क्र.सं.	क्षेत्र	पूंजी निवेश सब्सिडी की दरें (सीआईएस)	अलग—अलग इकाई के अनुसार सीआईएस
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	पात्र मशीनों पर 15%	30 करोड़ रु.*
2.	एकदम नए शटल—रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	पात्र मशीनों पर 10%	20 करोड़ रु.*
3(क)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्रों — यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	पात्र मशीनों पर 15%	30 करोड़ रु.*
3(ख)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्रों — यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश 50% से कम है तो सब्सिडी सीमा 20 करोड़ रु. होगी।	पात्र मशीनों पर 10%	20 करोड़ रु.*

\* यदि आवेदक ने पूर्व में आरआरटप्स के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कर ली हो, तो वह किसी एकल कंपनी के लिए संपूर्ण निर्धारित सीमा के अंतर्गत शेष राशि के लिए ही पात्र होगा।

एटफ्स के अंतर्गत एक एकल कंपनी हेतु समग्र निवेश के लिए अधिकतम सब्सिडी को 30 करोड़ रु. तक सीमित किया जाएगा।

5. योजना के विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

#### आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपियाँ संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को परिचालित की जाएं।

पुष्पा सुब्रहमण्यम  
अपर सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 13th January 2016

## RESOLUTION

No. 6/5/2015-TUFS—In order to promote ease of doing business in the country and achieve the vision of the Government for generation of employment and promotion of exports through “Make in India” and of Zero effect and Zero defect manufacturing, it has been decided that the existing provisions of the Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (RRTUFS) be modified in terms of the benefits under the scheme and the procedure for claiming the benefits under the scheme. A new scheme, “Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS)” has been approved by the Government for implementation which will provide one time capital subsidy for investments in the employment and technology intensive segments of the textile value chain keeping in view promotion of exports and imports substitution. The scheme will be credit linked and projects for technology upgradation covered by a prescribed limit of term loans sanctioned by the lending agencies will only be eligible for grant of benefits under it.

2. This scheme will be effective from the date of issue of this Resolution for a period of seven years upto 31.03.2022. However, the cases pending for issue of Unique Identification Number (UID) since September, 2014 as per records maintained by the Office of the Textile Commissioner shall be covered under the existing RRTUFS Scheme.

3. Entities/Units registered under the Companies Act with the Registrar of the Companies, except for MSME units which will be guided by the instructions of the Ministry of MSME or registered with the concerned Directorate of Industries/ relevant Department of the State Government will only be eligible to get the benefits under this scheme.

4. Every individual entity will be eligible for one time Capital Subsidy only, on the eligible investment, as per the rates and the overall subsidy cap indicated below:

Sl. No.	Segment	Rate of Capital Investment Subsidy (CIS)	CIS per individual entity
1.	Garmenting, Technical Textiles	15% on eligible Machines	Rs. 30 crore*
2.	Weaving for brand new Shuttle-less Looms (including weaving preparatory and knitting), Processing, Jute, Silk and Handloom.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*
3(a)	Composite unit /Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is more than 50% of the eligible project cost.	15% on eligible Machines	Rs. 30 crore*
3(b)	Composite unit/ Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is less than 50%, then the subsidy cap will be Rs. 20 crore.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*

\*In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity.

The maximum subsidy for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted to Rs. 30 crore.

5. The detailed guidelines of the scheme will be issued separately.

**ORDER**

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries / Departments / Organizations.

PUSHPA SUBRAHMANYAM  
Additional Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)